

1991 के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा में अंतर होने के बावजूद आर्थिक नीतियों में आई निरंतरता का अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार मीना

सहायक आचार्य

राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मासलपुर, करौली (राज.)

शोध-सार (Abstract)

वर्ष 1991 भारत के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास में एक युगांतरकारी मोड़ सिद्ध हुआ। गंभीर भुगतान संतुलन संकट (Balance of Payments Crisis) के जवाब में आरंभ किए गए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) के सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूलभूत ढांचे को बदल दिया। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य यह विश्लेषित करना है कि वर्ष 1991 के पश्चात् भारत में दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी और क्षेत्रीय - विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं वाले राजनीतिक दलों की सरकारों के गठन के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नीतियों में एक उल्लेखनीय और अभूतपूर्व निरंतरता क्यों और कैसे बनी रही।

यह पत्र कांग्रेस नीत नरसिम्हा राव सरकार (1991-1996), संयुक्त मोर्चा की सरकारों (1996-1998), अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार (1998-2004), मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार (2004-2014) तथा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (2014 से वर्तमान) के आर्थिक निर्णयों का तुलनात्मक और संस्थागत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन के निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि वैश्वीकरण का बाह्य दबाव, तकनीकी प्रगति, वित्तीय घाटे का नियंत्रण, नौकरशाही की निरंतरता, जनसांख्यिकीय मांगों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IMF, World Bank, WTO) की शर्तें ऐसे मुख्य कारक रहे हैं जिन्होंने वैचारिक मतभेदों को गौण कर दिया। यद्यपि चुनावी भाषणों और घोषणापत्रों में उग्र वैचारिक विरोध दिखाई देता है, परंतु सत्ता में आने पर सभी दल 'नव-उदारवादी आर्थिक आम सहमति' (Post-1991 Economic Consensus) का पालन करते हैं। यह शोध पत्र इस निरंतरता के सामाजिक-राजनीतिक परिणामों, क्रमिक सुधार मॉडल (Incremental Reforms) और भारतीय लोकतंत्र पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: आर्थिक सुधार 1991, राजनीतिक विचारधारा, उदारीकरण, वैश्वीकरण, नीतिगत निरंतरता, नव-उदारवाद, गठबंधन राजनीति, वाशिंगटन सर्वसम्मति।

प्रस्तावना (Introduction)

लोकतांत्रिक प्रणालियों में राजनीतिक दल भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के अनुसार, जब कोई वामपंथी या कल्याणकारी दल सत्ता में आता है, तो वह राज्य के नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय को प्राथमिकता देता है; जबकि दक्षिणपंथी या बाजार-समर्थक दल के सत्ता में आने पर करों में कटौती, विनिवेश और बाजार की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि, 1991 के बाद के भारतीय राजनीतिक परिदृश्य ने इस पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती दी है।

वर्ष 1991 से पूर्व भारत में 'नेहरूवादी समाजवाद' या 'लाइसेंस-परमिट-कोटा राज' का प्रभाव था, जहां राज्य अर्थव्यवस्था के 'कमांडिंग हाइट्स' पर काबिज था। 1991 के जून महीने में जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र 3 सप्ताह के आयात के योग्य (लगभग 1.2 अरब डॉलर) रह गया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था के द्वार खोलने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।

1991 के बाद के 35 वर्षों में भारत ने असाधारण राजनीतिक अस्थिरता और विविधता देखी है। इस दौरान देश में केंद्र स्तर पर 10 से अधिक प्रधानमंत्री बने, जिनमें एक-दलीय अल्पमत सरकारें, बहु-दलीय गठबंधन सरकारें और पूर्ण बहुमत वाली सरकारें शामिल रहीं। इन सरकारों में कांग्रेस (मध्यमार्गी), भारतीय जनता पार्टी (दक्षिणपंथी/सांस्कृतिक राष्ट्रवादी), जनता दल व क्षेत्रीय दल (समाजवादी/जाति-आधारित) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) जैसी वामपंथी पार्टियां (बाहरी समर्थक के रूप में) शामिल रहीं।

आश्चर्यजनक रूप से, चुनावी मंचों पर एक-दूसरे की आर्थिक नीतियों की उग्र आलोचना करने के बावजूद, सत्ता की कमान संभालते ही इन सभी दलों ने 1991 में तय की गई आर्थिक दिशा को ही आगे बढ़ाया। इस घटनाक्रम को अर्थशास्त्रियों और राजनीतिशास्त्रियों द्वारा "राजनीतिक विरोध के बीच नीतिगत सर्वसम्मति" (Policy Consensus amid Political Antagonism) का नाम दिया गया। प्रस्तुत शोध पत्र इसी विरोधाभास का गहन अध्ययन करता है कि वैचारिक विविधता के बावजूद आर्थिक नीतियों में यह अटूट निरंतरता किस प्रकार बनी रही।

शोध की कार्यप्रणाली एवं सैद्धांतिक ढांचा (Methodology and Theoretical Framework)

यह शोध पत्र मुख्य रूप से गुणात्मक और विश्लेषणात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। आंकड़ों और तथ्यों का संकलन प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों से किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में भारत सरकार की बजटीय रिपोर्टें, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दस्तावेज, पंचवर्षीय योजनाएं और विभिन्न दलों के चुनाव घोषणापत्र शामिल हैं। द्वितीयक स्रोतों में प्रख्यात अर्थशास्त्रियों, राजनीतिक विश्लेषकों की पुस्तकें, शोध पत्र और संपादकीय लेख शामिल हैं।

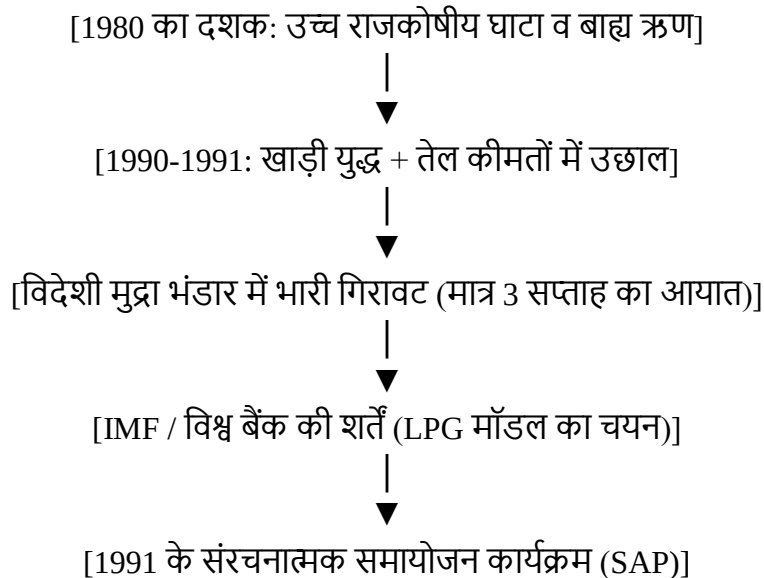
सैद्धांतिक ढांचा (Theoretical Framework)

इस अध्ययन को स्पष्टता प्रदान करने के लिए 4 प्रमुख सिद्धांतों का सहारा लिया गया है:

1. **वाशिंगटन सर्वसम्मति का सिद्धांत (Washington Consensus):** जॉन विलियमसन द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक व्यय का पुनर्प्राथमिकीकरण, कर सुधार, ब्याज दरों का उदारीकरण, प्रतिस्पर्धी विनिमय दर, व्यापार उदारीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा, निजीकरण और विनियमन को आधुनिक आर्थिक वृद्धि का आधार मानता है। भारत ने 1991 में अप्रत्यक्ष रूप से इसी मॉडल को अपनाया।
2. **पथ-निर्भरता का सिद्धांत (Path Dependency Theory):** पॉल डेविड और ब्रायन आर्थर द्वारा विकसित यह सिद्धांत बताता है कि जब कोई संस्था या राष्ट्र एक बार किसी विशिष्ट नीतिगत पथ का चयन कर लेता है, तो उस पथ से पीछे हटना या उसे बदलना अत्यधिक खर्चीला और जटिल हो जाता है। 1991 का सुधार भारत के लिए वही 'पथ' था।
3. **संरचनात्मक बाध्यता का सिद्धांत (Structural Constraint Theory):** वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में किसी भी देश की सरकार—चाहे उसकी विचारधारा कोई भी हो—अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों, साख रेटिंग एजेंसियों (Credit Rating Agencies) और बहुराष्ट्रीय पूंजी के दबाव से मुक्त होकर कार्य नहीं कर सकती।
4. **क्रमिक सुधार का सिद्धांत (Incrementalism Model):** चार्ल्स लिंडब्लोम का 'मुद्दों के समाधान का क्रमिक मॉडल' यह व्याख्या करता है कि लोकतांत्रिक समाजों में आमूल-चूल परिवर्तनों के बजाय छोटे-छोटे, निरंतर कदम उठाए जाते हैं ताकि जन-असंतोष से बचा जा सके। भारत के आर्थिक सुधार इसी 'शांत क्रमिकता' (Silent Incrementalism) के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

1991 के संकट का स्वरूप और आर्थिक सुधारों का आगाज

1991 का आर्थिक संकट कोई अकस्मात घटी घटना नहीं थी, बल्कि यह 1980 के दशक की अविवेकपूर्ण राजकोषीय नीतियों का दुष्परिणाम था। 1980 के दशक में सरकार ने जीडीपी के 8% से अधिक का राजकोषीय घाटा दर्ज किया, जिसकी भरपाई आंतरिक और बाह्य ऋणों से की गई। खाड़ी युद्ध (1990-1991) के कारण तेल की कीमतों में भारी उछाल आया और खाड़ी देशों से प्रवासियों द्वारा भेजा जाने वाला धन (Remittances) बंद हो गया।



1991 के सुधारों के तीन मुख्य स्तंभ:

- **उदारीकरण (Liberalization):** औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली (Licence Raj) को समाप्त करना, निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 18 से घटाकर केवल 8 (और बाद में 3) करना, तथा एमआरटीपी (MRTP) अधिनियम के कड़े प्रतिबंधों को हटाना।
- **निजीकरण (Privatization):** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) में सरकारी शेयर बेचना (विशिष्ट विनिवेश), निजी पूंजी को आकर्षित करना और राज्य के व्यावसायिक हस्तक्षेप को सीमित करना।
- **वैश्वीकरण (Globalization):** भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, आयात शुल्कों (Import Tariffs) में 300% से अधिक की कटौती करके उसे 150% और फिर 50% से नीचे लाना, तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के लिए स्वचालित मार्ग (Automatic Route) खोलना।

इन सुधारों को IMF के 'संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम' (Structural Adjustment Programme) के तहत लागू किया गया था। यद्यपि तत्कालीन विपक्ष (भाजपा और वामपंथी दलों) ने संसद में इसे "भारत की आर्थिक संप्रभुता को गिरवी रखना" करार दिया था, परंतु इतिहास ने सिद्ध किया कि सत्ता में आते ही इन दलों ने इन्हीं नीतियों को और अधिक गति से लागू किया।

विभिन्न कालखंडों में सरकारों का अध्ययन एवं नीतिगत निरंतरता

1991 से लेकर 2026 तक भारत में सत्ता परिवर्तन का लंबा इतिहास रहा है। इस अनुभाग में विभिन्न सरकारों के दौरान आर्थिक नीतियों की निरंतरता की विस्तृत जांच की गई है।

➤ नरसिम्हा राव सरकार (1991-1996): सुधारों की नींव

कांग्रेस पार्टी की यह अल्पमत सरकार 1991 में सत्ता में आई। अल्पमत में होने के बावजूद डॉ. मनमोहन सिंह और पी. वी. नरसिम्हा राव ने निम्नलिखित अभूतपूर्व कदम उठाए:

- रुपये का दो चरणों में 18% से 19% तक अवमूल्यन (Devaluation)।

- व्यापार नीति में सुधार और आयात लाइसेंसिंग की समाप्ति।
- वित्तीय क्षेत्र सुधारों के लिए नरसिम्हम समिति (1991) का गठन।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) को वैधानिक दर्जा प्रदान करना।

➤ **संयुक्त मोर्चा सरकारें (1996–1998): वामपंथियों की उपस्थिति के बावजूद 'ड्रीम बजट'**

1996 में 13 दलों के गठजोड़ से बनी संयुक्त मोर्चा सरकार को भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और अन्य वामपंथी दलों का बाहर से समर्थन प्राप्त था। एच. डी. देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल के प्रधानमंत्रित्व काल में चिदंबरम वित्त मंत्री बने।

- **1997 का 'ड्रीम बजट' (Dream Budget):** वामपंथियों के दबाव के बावजूद, चिदंबरम ने व्यक्तिगत आयकर की उच्चतम दर को 40% से घटाकर 30% और कॉर्पोरेट कर की दर को 45% से घटाकर 35% कर दिया।
- **FDI का विस्तार:** दूरसंचार, बिजली और पेट्रोलियम क्षेत्रों में ऑटोमैटिक रूट से 51% से 74% तक एफडीआई की अनुमति दी गई।
- **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA):** कड़े फेरा (FERA) कानून को निरस्त कर लचीले फेमा (FEMA) का मसौदा तैयार किया गया।

➤ **वाजपेयी नीत एनडीए सरकार (1998–2004): दक्षिणपंथी विचार और सुधारों को गति**

भाजपा ऐतिहासिक रूप से 'स्वदेशी' और 'व्यापारी वर्ग' के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी मानी जाती थी। सत्ता में आने से पूर्व भाजपा ने 'स्वदेशी जागरण मंच' के माध्यम से एफडीआई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारी विरोध किया था। परंतु, सत्ता संभालते ही अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सुधारों के द्वितीय चरण को आरंभ किया:

- **निजीकरण एवं पृथक मंत्रालय:** अरुण शौरी के नेतृत्व में भारत में पहली बार 'विनिवेश मंत्रालय' (Ministry of Disinvestment) बनाया गया। भारत एल्युमीनियम कंपनी (BALCO), हिंदुस्तान जिंक, मारुति सुजुकी और वीएसएनएल (VSNL) जैसी सार्वजनिक कंपनियों का रणनीतिक बिकवाली के जरिए निजीकरण किया गया।
- **अवसंरचना क्रांति:** राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (सर्वर्णिम चतुर्भुज) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई।
- **राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून:** 2003 में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (FRBM Act) पारित किया गया, जिसने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3% तक सीमित करने की कानूनी बाध्यता तय की।
- **दूरसंचार क्रांति:** 'न्यू टेलीकॉम पॉलिसी 1999' लाई गई, जिसने लाइसेंस शुल्क मॉडल को राजस्व-साझाकरण (Revenue Sharing) मॉडल में बदला, जिससे भारत में मोबाइल क्रांति का जन्म हुआ।

➤ **यूपीए 1 व 2 सरकारें (2004–2014): 'मानवीय चेहरे के साथ सुधार'**

2004 में वामपंथी दलों के 59 सांसदों के समर्थन पर निर्भर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार बनी। वामपंथ के भारी विरोध के बावजूद, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री चिदंबरम ने आर्थिक उदारीकरण के पथ को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे "समावेशी विकास" (Inclusive Growth) का नाम दिया:

- **भारत-अमेरिका परमाणु समझौता (2008):** इस समझौते पर अपनी सरकार बचाने के लिए मनमोहन सिंह ने वामपंथी दलों का समर्थन वापस लेना तक स्वीकार कर लिया, जो यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व सामरिक एकीकरण दलगत राजनीति से ऊपर था।
- **कल्याणकारी पूंजीवाद:** मनरेगा (MGNREGA - 2005), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (2005) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013) जैसी विशाल कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। इन योजनाओं का वित्तपोषण

1991 के बाद प्राप्त उच्च जीडीपी वृद्धि दर (जो 2004-2008 के बीच औसतन 8% से 9% रही) से प्राप्त कर राजस्व के माध्यम से ही संभव हो सका।

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST) का खाका:** यूपीए सरकार ने ही देशव्यापी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली (GST) और प्रत्यक्ष कर कोड (DTC) की नींव रखी।

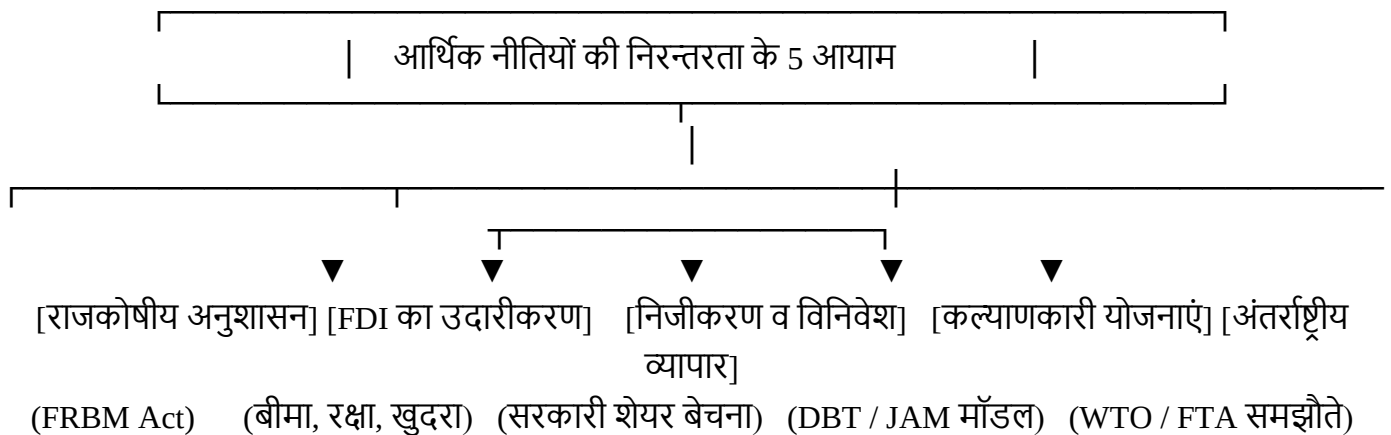
➤ एनडीए सरकार (2014 से वर्तमान): 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' और डिजिटल पूंजीवाद

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला। हालांकि चुनाव से पूर्व भाजपा ने यूपीए की आधार योजना और जीएसटी का विरोध किया था, परंतु सत्ता में आते ही इन नीतियों को अभूतपूर्व पैमाने पर लागू किया गया:

- **वस्तु एवं सेवा कर (GST - 2017):** 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को लागू किया गया, जो 1991 के बाद का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है।
- **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC - 2016):** कॉर्पोरेट ऋण समाधान और बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) से निपटने के लिए एक आधुनिक ढांचा तैयार किया गया।
- **बैंकिंग और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):** जन धन योजना, आधार और मोबाइल (JAM त्रिमूर्ति) के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का सीधा वितरण किया गया, जिसने रिसाव को रोका।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI Scheme):** विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अरबों डॉलर के प्रोत्साहन दिए गए।
- **रणनीतिक निजीकरण:** एअर इंडिया (Air India) का टाटा समूह को सफल हस्तांतरण और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (IPO) लाया गया।

नीतिगत निरंतरता के मुख्य विषयगत आयाम

विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के पैटर्न का अध्ययन करने पर 5 प्रमुख क्षेत्र स्पष्ट रूप से सामने आते हैं जहां विचारधाराओं का अंतर पूरी तरह मिट गया:



➤ राजकोषीय अनुशासन एवं कराधान सुधार

चाहे 2003 का FRBM अधिनियम हो या 2016 का मुद्रण व मौद्रिक नीति ढांचा (Monetary Policy Framework), सभी सरकारों ने मुद्रास्फीति नियंत्रण (Inflation Targeting - 4% (+/- 2%)) और राजकोषीय घाटे को कम करने को प्राथमिकता दी है। प्रत्यक्ष करों का सरलीकरण और अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण (GST) सभी दलों का सांझा एजेंडा रहा है।

➤ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का उदारीकरण

1991 में एफडीआई की सीमा अधिकांश क्षेत्रों में 51% थी। आज रक्षा, बीमा, सिविल एविएशन, टेलीकॉम और एकल ब्रांड खुदरा व्यापार में 74% से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। जो दल विपक्ष में रहते हुए

एफडीआई का विरोध करते हैं (जैसे खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का भाजपा द्वारा 2012 में विरोध), वही सत्ता में आने पर इसका दायरा और बढ़ा देते हैं।

➤ 6.3 निजीकरण, विनिवेश और संपत्ति मौद्रिकरण

1991 के बाद सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी पूंजी को निकालने (Disinvestment) की नीति पर सभी सरकारें चली हैं। राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन (National Monetization Pipeline) के माध्यम से एनडीए सरकार ने बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों से निजी पूंजी जुटाने का जो खाका खींचा है, वह 1990 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण का ही अगला चरण है।

➤ 6.4 प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) और डिजिटल अवसंरचना

1980 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने स्वीकार किया था कि "दिल्ली से भेजा गया 1 रुपया धरातल पर पहुँचते-पहुँचते 15 पैसे रह जाता है।" 1991 के बाद बनी सरकारों ने इस रिसाव को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लिया। यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई 'आधार' (Aadhaar) परियोजना को एनडीए सरकार ने 'जन धन योजना' से जोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल वित्तीय समावेशन ढांचा तैयार किया।

➤ 6.5 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वैश्विक एकीकरण

सभी राजनीतिक दलों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पालन किया है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर निकलने जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (ASEAN), संयुक्त अरब अमीरात (UAE), ऑस्ट्रेलिया और मॉरीशस के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) किए हैं, जो अर्थव्यवस्था के क्रमिक वैश्विक एकीकरण को दर्शाते हैं।

राजनीतिक दलों की नीतियों का कालानुक्रमिक व तुलनात्मक विश्लेषण

नीचे दी गई तालिका 1991 के बाद की प्रमुख सरकारों, उनकी राजनीतिक विचारधाराओं और उनके द्वारा अपनाई गई प्रमुख आर्थिक नीतियों की निरंतरता को दर्शाती है:

कालखंड	सरकार / गठबंधन	मुख्य राजनीतिक विचारधारा	प्रमुख आर्थिक नीतिगत निर्णय	निरंतरता का सूचक
1991 – 1996	कांग्रेस (नरसिम्हा राव)	मध्यमार्गी (Center-Left)	औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, आयात शुल्क में कटौती, सेबी को वैधानिक दर्जा।	1991 के सुधारों का प्रारंभ।
1996 – 1998	संयुक्त मोर्चा (देवेगौड़ा / गुजराल)	वाम-केंद्रित व क्षेत्रीय दल	'ड्रीम बजट' 1997, कर दरों में कटौती, FEMA का मसौदा, FDI का विस्तार।	वामपंथ के समर्थन के बावजूद सुधार जारी।
1998 – 2004	NDA - 1 (अटल बिहारी वाजपेयी)	दक्षिणपंथी / सांस्कृतिक राष्ट्रवाद	विनिवेश मंत्रालय, FRBM एक्ट 2003, स्वर्णिम चतुर्भुज, दूरसंचार नीति 1999।	'स्वदेशी' विचार के बावजूद निजीकरण की तीव्र गति।
2004 – 2014	UPA - 1 व 2 (मनमोहन सिंह)	मध्यमार्गी / सामाजिक-लोकतांत्रिक	परमाणु समझौता, जीएसटी का खाका, मनरेगा, एफडीआई विस्तार (बीमा व खुदरा)।	वामपंथी दबाव के बावजूद वैश्विक एकीकरण।
2014 – वर्तमान	NDA - 2 व 3 (नरेंद्र मोदी)	दक्षिणपंथी / दक्षिणपंथी-लोकलुभावन	GST 2017, IBC 2016, एअर इंडिया निजीकरण, PLI योजना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।	उदारीकरण और बाजार-संचालित सुधारों का चरम।

(स्रोत: भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षणों और बजटीय आंकड़ों का संकलित अध्ययन)

वैचारिक भिन्नता के बावजूद निरंतरता के मुख्य कारण (Drivers of Continuity)

राजनीतिक दलों के विचारों में गहरे मतभेद होने के बावजूद नीतियों में यह एकरूपता क्यों पाई जाती है? इसके पीछे निम्नलिखित 6 प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं:

- [1. वैश्वीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं (IMF, WB, WTO)]
- |
- [2. भारत की मजबूत और स्थायी नौकरशाही (Bureaucratic Continuity)]
- |
- [3. राजकोषीय एवं बजटीय वास्तविकताएं (Fiscal Constraints)]
- |
- [4. भारतीय मध्यम वर्ग का दबाव और आकांक्षाएं (Middle Class Growth)]
- |
- [5. राज्यों के बीच 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism)]
- |
- [6. कॉर्पोरेट फंडिंग और राजनीतिक वित्तपोषण (Corporate Lobbying)]

➤ 8.1 वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत दबाव

1991 के बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से पूरी तरह जुड़ गया। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (जैसे Moody's, S&P, Fitch) का दबाव किसी भी सरकार को नीतिगत भटकाव की अनुमति नहीं देता। यदि कोई सरकार उदारीकरण की नीतियों से पीछे हटती है, तो देश से पूंजी का पलायन (Capital Flight) होने और साख रेटिंग घटने का खतरा रहता है, जिससे रुपया गिर सकता है।

➤ 8.2 संस्थागत एवं नौकरशाही की निरंतरता (Bureaucracy)

भारत में 'स्थायी कार्यपालिका' (भारतीय प्रशासनिक सेवा - IAS) नीति निर्माण और कार्यान्वयन का मुख्य तंत्र है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA), आरबीआई गवर्नर, वित्त सचिव और नीति आयोग के सदस्य अक्सर वही अर्थशास्त्री या अधिकारी होते हैं जो विभिन्न सरकारों के दौर में अपनी सेवाएं देते हैं। यह नौकरशाही संरचना किसी भी सरकार को मौलिक रूप से लीक से हटने नहीं देती।

➤ 8.3 राजकोषीय वास्तविकताएं और संसाधन संकट

जब दल विपक्ष में होते हैं, तो वे लोकलुभावन वादे करते हैं। परंतु सत्ता में आते ही उन्हें राजस्व की कमी और राजकोषीय घाटे की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कल्याणकारी योजनाओं, रक्षा व्यय और अवसंरचना के लिए धन जुटाने का एकमात्र तरीका कर राजस्व बढ़ाना, एफडीआई आकर्षित करना और परिसंपत्तियों का विनिवेश करना ही बचता है।

➤ 8.4 मध्यम वर्ग का विस्तार और जनसांख्यिकीय मांगें

1991 के सुधारों के बाद भारत में एक विशाल मध्यम वर्ग (लगभग 30 से 40 करोड़ लोग) का उदय हुआ है। यह वर्ग बेहतर उपभोक्ता वस्तुओं, डिजिटल सेवाओं, बेहतर नौकरियों और विश्वस्तरीय अवसंरचना की मांग करता है। कोई भी राजनीतिक दल इस विशाल और मुखर वोट बैंक को नाराज करके पुरानी बंद अर्थव्यवस्था की ओर नहीं लौट सकता।

➤ 8.5 'प्रतिस्पर्धी संघवाद' (Competitive Federalism)

1991 के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह समझ आ गया कि केवल केंद्रीय अनुदान के भरोसे राज्य का विकास नहीं हो सकता। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल (तृणमूल कांग्रेस/पूर्व में वाममोर्चा), ओडिशा (बीजू जनता दल), तमिलनाडु (DMK/AIADMK), तेलंगाना (TRS) और गुजरात (भाजपा) जैसे राज्यों के बीच अपने-

अपने राज्यों में निजी निवेश और औद्योगिक पूंजी आकर्षित करने की होड़ मच गई। राज्यों के इस प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार ने राष्ट्रीय स्तर पर सुधारों को स्थायित्व प्रदान किया।

➤ 8.6 राजनीतिक वित्तपोषण और कॉर्पोरेट प्रभाव

आधुनिक चुनावी राजनीति अत्यधिक खर्चीली हो चुकी है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों के लिए निजी कॉर्पोरेट घराने और उद्योगपतियों के चंदे पर निर्भर हैं। इस आर्थिक निर्भरता के कारण कोई भी दल सत्ता में आने के बाद बाजार-विरोधी या कॉर्पोरेट-विरोधी नीतियां लागू नहीं कर सकता।

आलोचनात्मक मूल्यांकन और सामाजिक-राजनीतिक परिणाम

यद्यपि 1991 के बाद की नीतिगत निरंतरता ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मदद की है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1991 के 1.2 अरब डॉलर से बढ़कर 600 अरब डॉलर के पार पहुँचा है, परंतु इसके गंभीर सामाजिक-राजनीतिक दुष्परिणाम भी सामने आए हैं:

➤ 9.1 लोकतांत्रिक विकल्पों का क्षरण (Depoliticization of Economics)

जब सभी दल सत्ता में आने पर एक ही जैसी आर्थिक नीतियां अपनाते हैं, तो मतदाताओं के सामने वास्तविक 'आर्थिक विकल्प' समाप्त हो जाता है। नागरिक जिस पार्टी को भी वोट दें, परिणाम वही नव-उदारवादी नीतियां होती हैं। राजनीतिशास्त्री प्रताप भानु मेहता के अनुसार, इससे अर्थव्यवस्था का "गैर-राजनीतिकरण" (Depoliticization) हो गया है, जहां बुनियादी आर्थिक फैसले जनता के बजाय तकनीकी विशेषज्ञों (Technocrats) द्वारा लिए जाते हैं।

➤ 9.2 बढ़ती आर्थिक असमानता (Economic Inequality)

विश्व असमानता रिपोर्ट (World Inequality Report) के अनुसार, भारत में 1991 के बाद आय और संपत्ति की असमानता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। देश की शीर्ष 1% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा केंद्रित हो गया है। आर्थिक नीतियों की निरंतरता ने संपत्ति के इस संकेंद्रण को रोकने के लिए पर्याप्त कर या पुनर्वितरण उपाय नहीं किए हैं।

➤ 9.3 वास्तविक वैचारिक बहसों का सांस्कृतिक/पहचान की राजनीति में रूपांतरण

जब प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आर्थिक नीतियों पर विरोध का कोई बड़ा आधार नहीं बचता, तो वे मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए गैर-आर्थिक मुद्दों का सहारा लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जैसे ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दों का वर्चस्व बढ़ गया है।

➤ 9.4 'क्रोनी पूंजीवाद' (Crony Capitalism) का उदय

निजीकरण और प्राकृतिक संसाधनों (जैसे स्पेक्ट्रम, कोयला खदानें, भूमि) के आवंटन की निरंतर नीति ने कई बार 'क्रोनी पूंजीवाद' को जन्म दिया है, जहां चुनिंदा उद्योगपतियों का राज्य के संसाधनों पर एकाधिकार स्थापित हो गया है।

10. निष्कर्ष एवं सिफारिशें (Conclusion and Recommendations)

निष्कर्ष

1991 के पश्चात् भारतीय राजनीति के अध्ययन से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि विचारधारात्मक मतभेद अब केवल चुनावी बयानबाजी और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों तक सीमित रह गए हैं। आर्थिक नीतियों के धरातल पर भारत में एक मजबूत, टिकाऊ और सर्वदलीय "नव-उदारवादी आम सहमति" स्थापित हो चुकी है।

यह निरंतरता भारत के लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों सिद्ध हुई है। वरदान इस अर्थ में कि इसने भारत को एक स्थिर, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया, जहां सरकारों के बदलने से विदेशी निवेश और दीर्घकालिक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अभिशाप इस अर्थ में कि

इसने देश में आर्थिक असमानता को बढ़ाया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वास्तविक आर्थिक विकल्पों को गायब कर दिया है।

भारत की आर्थिक नीतियों का यह क्रमिक विकास यह दर्शाता है कि 21वीं सदी में व्यावहारिक जरूरतें (Pragmatism) हमेशा वैचारिक कट्टरता (Ideological Dogmatism) पर विजय प्राप्त करती हैं।

सिफारिशें (Recommendations)

1. **समावेशी वृद्धि पर बल:** भविष्य की नीतिगत निरंतरता में केवल जीडीपी वृद्धि को ही नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और आय असमानता को कम करने को मुख्य सूचकांक बनाया जाना चाहिए।
2. **संसद में आर्थिक नीतियों पर विस्तृत बहस:** आर्थिक सुधारों को अध्यादेशों या बिना बहस के पास कराने के बजाय संसदीय स्थायी समितियों (Parliamentary Standing Committees) के माध्यम से सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए।
3. **स्थानीय स्तर पर उदारीकरण का लाभ:** आर्थिक सुधारों का लाभ केवल कॉर्पोरेट क्षेत्र और महानगरों तक सीमित न रहकर कृषि क्षेत्र, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) और ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक पहुँचाया जाना अनिवार्य है।
4. **कल्याणकारी और बाजार नीतियों का संतुलन:** भारत को पूर्णतः बाजार-संचालित मॉडल अपनाने के बजाय एक मजबूत 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) के रूप में स्वास्थ्य और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के कम से कम 3% और 6% तक बढ़ाना चाहिए।

संदर्भ सूची (References)

1. **अहलुवालिया, मोटेक सिंह.** (2002). *आर्थिक सुधार: 1991 के बाद का अनुभव*. जर्नल ऑफ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, खंड 16, संख्या 3, पृष्ठ 67–88।
2. **अहलुवालिया, मोटेक सिंह.** (2020). *बैकस्टेज: द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज हाई ग्रोथ इयर्स*. रूपा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
3. **बर्धन, प्रणब.** (1998). *द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया*. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
4. **भादुड़ी, अमित और नायक, दीपक.** (1996). *द इंटेलेजेंट पर्सन्स गाइड टू लिबरलाइजेशन*. पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली।
5. **भागवती, जगदीश और पनगड़िया, अरविंद.** (2012). *भारत का सुधार पथ: विकास और समावेश की दिशा*. रैंडम हाउस इंडिया।
6. **जोशी, विजय और लिटिल, आई.एम.डी.** (1996). *इण्डियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991–2001*. क्लैरेंडन प्रेस, ऑक्सफोर्ड।
7. **कोहली, अतुल.** (2012). *पॉवर्टी अमिट प्लेंटी इन इंडिया: द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ न्यू लिबरल पॉलिसीज*. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।
8. **मोहन, राकेश.** (2008). *इण्डियाज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स: फॉरवर्ड लुकिंग बाय लुकिंग बैक*. आरबीआई बुलेटिन, मुंबई।
9. **नागराज, आर.** (2006). *इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 41, संख्या 11।
10. **पंत, अरविंद.** (2015). *भारतीय अर्थव्यवस्था: उदारीकरण के बाद का दौर*. अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
11. **पटनायक, प्रभात.** (2007). *द वैल्यू ऑफ मनी*. कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयॉर्क।

12. रोडरिक, दानी और सुब्रमण्यम, अरविंद. (2005). फ्रॉम "हिन्दू ग्रोथ" टू Productivity Surge: द मिस्ट्री ऑफ द इंडियन ग्रोथ ट्रांजिशन. आईएमएफ स्टाफ पेपर्स, खंड 52, संख्या 2।
13. सेन, अमर्त्य और ड्रेज, जीन. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शंस. पेंगुइन बुक्स, लंदन।
14. सिंह, एम. पी. और रॉय, हिमांशु. (2018). भारतीय राजनीतिक प्रणाली: संरचना एवं प्रक्रिया. टाटा मैकग्रा हिल, नई दिल्ली।
15. श्रीनिवासन, टी. एन. और तेंदुलकर, सुरेश डी. (2003). रीइंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू द वर्ल्ड इकॉनमी. पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स।
16. वरमा, ए. के. (2018). पॉलिसी कन्सेप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स post-1991. भारतीय राजनीति विज्ञान पत्रिका, खंड 79, संख्या 2।
17. वाधवा, चरण डी. (1994). इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड द मार्केट इकॉनमी. एलाइड पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
18. यंग, जॉन. (2011). द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग नेशंस. रूटलेज, लंदन।
19. जयल, नीरजा गोपाल और मेहता, प्रताप भानु. (2010). द ऑक्सफोर्ड कम्पेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
20. रुडोल्फ, लॉयड आई. और रुडोल्फ, सुज़ैन एच. (2008). इन्पर्स ऑफ लक्ष्मी: द पॉलिटिकल इकॉनमी ऑफ द इंडियन स्टेट. यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो प्रेस।
21. चक्रवर्ती, सुकुमार. (1987). डेवलपमेंट प्लानिंग: द इंडियन एक्सपीरियंस. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
22. चौधरी, मृणाल. (1993). मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इन इंडिया. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 28, संख्या 35।